शोधामृत
(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-4.0
Vol.-3; issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No- 205-211
©2026 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

Author's :

सुरेश कुमार
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान,
राजकीय कला महाविद्यालय सीकर,
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर.

Corresponding Author :

सुरेश कुमार
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान,
राजकीय कला महाविद्यालय सीकर,
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर.

भूराजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में ब्रिक्स विस्तार : भारत के समक्ष अवसर व रणनीतिक चुनौतियाँ

सारांश : इक्कीसवीं सदी में वैश्विक राजनीति तीव्र भूराजनीतिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। शीत युद्धोत्तर एकध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व प्रमुख रहा, अब बहुध्रुवीय शक्ति-संतुलन की ओर परिवर्तित हो रही है। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा राजनीति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन तथा ग्लोबल साउथ के उभार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा को पुनर्परिभाषित किया है। इसी परिवर्तित परिदृश्य में ब्रिक्स का विस्तार एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटना के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक शक्ति-संरचना पर व्यापक प्रभाव डाला है। ब्रिक्स का मूल उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था, किंतु समय के साथ यह मंच वैश्विक शासन, वित्तीय संरचना सुधार तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का एक प्रमुख वाहक बन गया। हालिया विस्तार के माध्यम से नए सदस्य देशों के जुड़ने से ब्रिक्स की सामरिक, आर्थिक और ऊर्जा-संबंधी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे यह समूह पश्चिम-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय संस्थागत ढांचे के समांतर एक प्रभावशाली वैकल्पिक मंच के रूप में स्थापित हो रहा है। विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को संगठित रूप देने और विकासशील देशों की आवाज को सशक्त करने में ब्रिक्स विस्तार का महत्त्व बढ़ गया है। भारत के लिए ब्रिक्स विस्तार अवसरों और चुनौतियों का सम्मिलित स्वरूप प्रस्तुत करता है। एक ओर यह मंच भारत को बहुध्रुवीय व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने, वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व स्थापित करने तथा ऊर्जा और आर्थिक सहयोग के नए आयाम विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रिक्स के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं और वैकल्पिक विकास तंत्रों का सुदृढ़ीकरण भारत की विकास प्राथमिकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूती दे सकता है। दूसरी ओर, भारत के समक्ष कई रणनीतिक चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। ब्रिक्स के भीतर चीन की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति भारत की स्वतंत्र भूमिका को प्रभावित कर

सकती है। सीमा-विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जैसे कारक दोनों देशों के संबंधों को जटिल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, रूस-पश्चिम तनाव की पृष्ठभूमि में रूस की स्थिति तथा भारत के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते सामरिक संबंध संतुलन की चुनौती उत्पन्न करते हैं। भारत को एक ओर ब्रिक्स के भीतर सक्रिय रहना है, तो दूसरी ओर क्वाड, जी-20 और इंडो-पैसिफिक साझेदारियों में भी अपनी भूमिका बनाए रखनी है। ब्रिक्स विस्तार की विविधता और सदस्य देशों की भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएँ भी समूह की एकता और प्रभावशीलता के लिए चुनौती बन सकती हैं। यदि समूह किसी विशेष शक्ति के प्रभाव में आ जाता है या आंतरिक मतभेद बढ़ते हैं, तो भारत के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना कठिन हो सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भूराजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक शक्ति-संरचना में संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर है, किंतु इसका लाभ उठाने हेतु संतुलित कूटनीति, सामरिक स्वायत्तता और बहुस्तरीय विदेश नीति का विवेकपूर्ण संचालन आवश्यक है।

मुख्य शब्द : ब्रिक्स विस्तार, भूराजनीति, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, भारत की विदेश नीति, वैश्विक शक्ति संतुलन, सामरिक स्वायत्तता, ग्लोबल साउथ।

प्रस्तावना : इक्कीसवीं सदी की वैश्विक राजनीति गहरे भूराजनीतिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात स्थापित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों का वर्चस्व प्रमुख था, अब बहुध्रुवीय शक्ति-संतुलन की ओर अग्रसर है। अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस -यूक्रेन संघर्ष, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की राजनीति, तथा ग्लोबल साउथ के उभार जैसे कारकों ने वैश्विक शक्ति-संरचना को पुनर्परिभाषित किया है। इन परिवर्तनों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक जटिल, बहुस्तरीय और प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। ऐसे परिवेश में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का उभार और उसका हालिया विस्तार वैश्विक राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आया है। प्रारंभिक रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में स्थापित ब्रिक्स आज वैश्विक शासन, वित्तीय संरचना सुधार और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का एक प्रभावशाली कूटनीतिक मंच बन चुका है। ब्रिक्स विस्तार का अर्थ ब्रिक्स समूह के उस विस्तार से है, जिसके अंतर्गत मूल पाँच सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त नए देशों को औपचारिक सदस्यता प्रदान की गई। यह विस्तार 2023 के शिखर सम्मेलन (जोहान्सबर्ग) के बाद प्रभावी हुआ और 1 जनवरी 2024 से नए सदस्य देशों ने ब्रिक्स में प्रवेश किय[1]।

ब्रिक्स विस्तार का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व, आर्थिक-सामरिक सहयोग के विस्तार तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके माध्यम से ब्रिक्स केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच न रहकर एक व्यापक भू-राजनीतिक समूह के रूप में विकसित हो रहा है। इसके विस्तार के माध्यम से नए सदस्य देशों का समावेश न केवल इसकी आर्थिक और जनसांख्यिकीय शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि इसे भू-राजनीतिक दृष्टि से अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाता है। ब्रिक्स विस्तार को पश्चिम-केंद्रित वैश्विक व्यवस्था के समांतर एक वैकल्पिक शक्ति-संरचना के निर्माण के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। यह कदम विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता देशों के एक मंच पर आने से वैश्विक ऊर्जा राजनीति में भी नए समीकरण उभर रहे हैं। भारत के संदर्भ में ब्रिक्स विस्तार विशेष महत्त्व रखता है। भारत एक ओर इस मंच को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है, वहीं दूसरी ओर उसे चीन के बढ़ते प्रभाव, रूस - पश्चिम तनाव, और अपनी "रणनीतिक स्वायत्तता" बनाए रखने की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत की विदेश नीति आज संतुलनकारी कूटनीति पर आधारित है, जिसमें वह ब्रिक्स, क्वाड, जी- 20 तथा

अन्य बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, भूराजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में ब्रिक्स का विस्तार केवल एक संस्थागत विकास नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन के पुनर्संरचना की प्रक्रिया का संकेतक है[2]। भारत के लिए यह अवसरों और चुनौतियों का सम्मिलित परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसके विश्लेषण की आवश्यकता इस शोध के माध्यम से की जा रही है।

बदलते भूराजनीतिक परिवेश की विशेषताएँ : इक्कीसवीं सदी का वैश्विक परिदृश्य तीव्र परिवर्तन और पुनर्संरचना की प्रक्रिया से गुजर रहा है। पारंपरिक शक्ति-संतुलन की अवधारणा अब बहुस्तरीय प्रतिस्पर्धा, आर्थिक परस्पर निर्भरता और तकनीकी प्रभुत्व के नए आयामों से प्रभावित हो रही है। बदलते भूराजनीतिक परिवेश की प्रमुख विशेषताएँ हैं -

1. एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर संक्रमण - शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका-प्रधान एकध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई थी, किंतु वर्तमान में चीन, भारत, रूस और यूरोपीय संघ जैसी शक्तियों के उभार ने शक्ति-संरचना को बहुध्रुवीय बना दिया है। वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया अब एक ही शक्ति पर केंद्रित न रहकर विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच विभाजित हो रही है।
2. अमेरिका -चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा - 21 वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भूराजनीतिक प्रवृत्ति अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। यह प्रतिस्पर्धा व्यापार, प्रौद्योगिकी, सैन्य संतुलन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार से जुड़ी है। इसका प्रभाव वैश्विक संस्थाओं, गठबंधनों और आर्थिक संरचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है।
3. रूस-यूक्रेन संघर्ष और शक्ति-संतुलन का पुनर्गठन- रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा संरचना, ऊर्जा राजनीति और वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित किया है। इससे नाटो की भूमिका पुनः सशक्त हुई है तथा रूस और पश्चिम के संबंधों में गंभीर तनाव उत्पन्न हुआ है। इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ा है।
4. ग्लोबल साउथ का उदय - विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अब वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार की मांग कर रही हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का आर्थिक और जनसांख्यिकीय महत्व बढ़ने से वैश्विक विमर्श में उनकी आवाज अधिक प्रभावशाली हो रही है। यह प्रवृत्ति ब्रिक्स जैसे मंचों को सशक्त बनाती है।
5. आर्थिक भू-राजनीति और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना - कोविड- 19 महामारी, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हुआ है। देश अब "मित्र-देश आपूर्ति" और "आत्मनिर्भरता" की नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे आर्थिक संबंधों का राजनीतिकरण बढ़ा है।
6. ऊर्जा और संसाधन-आधारित राजनीति - ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस संसाधनों पर नियंत्रण तथा हरित ऊर्जा संक्रमण वर्तमान भू-राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व बन चुके हैं। ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच नए गठबंधन उभर रहे हैं।
7. बहुपक्षीय संस्थाओं सुधार की मांग - संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग तेज हुई है। विकासशील देशों का तर्क है कि वर्तमान संस्थागत ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति-संरचना को प्रतिबिंबित करता है, जो आज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता।
8. प्रौद्योगिकी और साइबर शक्ति का महत्व - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर तकनीक जैसी नई तकनीकों ने शक्ति-संतुलन के नए आयाम जोड़े हैं। तकनीकी श्रेष्ठता अब वैश्विक प्रभुत्व का प्रमुख साधन बन चुकी है। क्षेत्रीय संगठनों और वैकल्पिक मंचों का उभार ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, जी- 20 तथा अन्य क्षेत्रीय मंच वैश्विक शासन की नई संरचना का संकेत देते हैं। ये मंच पारंपरिक पश्चिम-केंद्रित संस्थाओं के समांतर नई संभावनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

9. सामरिक स्वायत्तता और संतुलनकारी कूटनीति - कई देश अब किसी एक शक्ति-गुट के साथ पूर्ण रूप से संरेखित होने के बजाय संतुलनकारी नीति अपना रहे हैं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से भारत जैसे देशों में देखी जा सकती है, जो विभिन्न वैश्विक मंचों पर सक्रिय रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं।

ब्रिक्स विस्तार का भू-राजनीति पर प्रभाव : भूराजनीतिक परिवर्तनों के वर्तमान संदर्भ में ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक शक्ति-संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। प्रारम्भ में केवल पाँच देशों -ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तक सीमित यह समूह अब अपने विस्तार के बाद एक व्यापक बहुध्रुवीय मंच के रूप में उभरा है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य शामिल हो चुके हैं। इन नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स की भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक पहुँच अत्यधिक विस्तृत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप यह समूह अब अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया तक प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विभिन्न समसामयिक अध्ययन यह संकेत करते हैं कि इस विस्तार के बाद ब्रिक्स विश्व की कुल जनसंख्या और ऊर्जा संसाधनों के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने लगा है, जिससे इसकी सामूहिक सौदेबाजी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ब्रिक्स विस्तार का एक प्रमुख भूराजनीतिक प्रभाव यह है कि यह पारंपरिक पश्चिम-प्रधान वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता हुआ एक वैकल्पिक शक्ति-केन्द्र के रूप में उभर रहा है। नए सदस्यों, विशेषकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के सम्मिलन से ऊर्जा-राजनीति में ब्रिक्स की भूमिका सुदृढ़ हुई है, क्योंकि ये देश वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी प्रकार मिस्र और इथियोपिया के शामिल होने से अफ्रीकी महाद्वीप में ब्रिक्स की रणनीतिक पकड़ मजबूत हुई है, जबकि इंडोनेशिया के जुड़ने से दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका प्रभाव बढ़ा है। इस प्रकार ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच न रहकर वैश्विक दक्षिण के देशों की सामूहिक राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनता जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा अधिक न्यायसंगत वैश्विक शासन की मांग करता है[3]।

इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक शक्ति-संरचना में बहुध्रुवीयता को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जो लंबे समय तक एकध्रुवीय या पश्चिम-केन्द्रित रही, अब धीरे-धीरे बहु-केन्द्रित स्वरूप ग्रहण कर रही है। ब्रिक्स के विस्तारित स्वरूप ने विकासशील देशों को एक साझा मंच प्रदान किया है, जिसके माध्यम से वे अपनी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में सुधार की मांग तथा वैकल्पिक वित्तीय तंत्र विकसित करने की पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। हालाँकि, इस विस्तार के साथ कुछ जटिलताएँ भी उत्पन्न हुई हैं, जो स्वयं भूराजनीतिक प्रभाव का हिस्सा हैं। विविध राजनीतिक प्रणालियों, क्षेत्रीय हितों और कूटनीतिक प्राथमिकताओं के कारण ब्रिक्स के भीतर नीति-समन्वय चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिर भी, इन विविधताओं के बावजूद, ब्रिक्स का विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक शक्ति-संतुलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ उभरती अर्थव्यवस्थाएँ और वैश्विक दक्षिण के देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर हैं। इस प्रकार, ब्रिक्स विस्तार न केवल एक संस्थागत परिवर्तन है, बल्कि यह समग्र रूप से वैश्विक भूराजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है।

भारत के समक्ष अवसर और रणनीतिक चुनौतिया : ब्रिक्स विस्तार से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिससे भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरने का अवसर मिलता है। भारत अपनी विकासात्मक उपलब्धियों, लोकतांत्रिक संरचना और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की नीति के आधार पर एक संतुलित नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बहुध्रुवीय विश्व में कूटनीतिक संतुलन भारत लंबे समय से "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति का समर्थक रहा है। ब्रिक्स मंच भारत को पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए वैकल्पिक शक्ति-केंद्रों विशेषतः रूस और चीन के साथ संवाद बनाए रखने का अवसर देता है। इससे भारत वैश्विक

मंचों पर संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स के नव-विस्तारित स्वरूप में प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश शामिल हैं जो भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश के नए अवसर प्रदान करती है। साथ ही, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से डॉलर पर निर्भरता कम करने की संभावनाएँ भी खुलती हैं। ब्रिक्स के माध्यम से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की मांग को सामूहिक रूप से उठा सकता है। इससे भारत के दीर्घकालिक वैश्विक शक्ति के लक्ष्य को बल मिलता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और अन्य सहयोगी तंत्रों के माध्यम से भारत अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक गुड्स, स्वास्थ्य एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ा सकता है।

चीन का बढ़ता प्रभाव : ब्रिक्स विस्तार में चीन की सक्रिय भूमिका भारत के लिए चुनौती उत्पन्न करती है। चीन ब्रिक्स समूह में आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली सदस्य है और अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप एजेंडा निर्धारित करने का प्रयास करता है। भारत-चीन सीमा विवाद और इंडो-पैसिफिक प्रतिस्पर्धा इस संतुलन को और जटिल बनाते हैं। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी तनाव का प्रभाव ब्रिक्स मंच पर भी पड़ सकता है। भारत को अपने पश्चिमी साझेदारों विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को संतुलित रखते हुए ब्रिक्स के भीतर सक्रिय भूमिका निभानी होती है। ब्रिक्स के सदस्य देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ, विदेश नीति प्राथमिकताएँ और आर्थिक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इस विविधता के कारण सामूहिक निर्णय-निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिससे समूह की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। भारत को इन विभिन्न हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। स्थानीय मुद्रा व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र का विकास एक अवसर है, किन्तु इससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता भी उत्पन्न हो सकती है[4]। भारत को अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे। भारत क्वाड, इंडो-पैसिफिक साझेदारी और अन्य पश्चिम-समर्थित मंचों का भी सदस्य है। ब्रिक्स में अत्यधिक झुकाव भारत की संतुलित विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। अतः "मल्टी-अलाइनमेंट" की नीति को व्यावहारिक बनाए रखना एक रणनीतिक चुनौती है। आंतरिक मतभेद - सदस्य देशों की विविध राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएँ ब्रिक्स समूह की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया वर्तमान वैश्विक परिदृश्य जिसमें बहुध्रुवीयता का उभार, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-पश्चिम तनाव, ऊर्जा संकट और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाएँ प्रमुख हैं। भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रित परिदृश्य प्रस्तुत करता है। ब्रिक्स के विस्तार के संदर्भ में भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया बहुआयामी, संतुलित एवं यथार्थवादी रही है। भारत ने परंपरागत गुटनिरपेक्ष विरासत को समकालीन "बहु-संरेखीय कूटनीति" में रूपांतरित किया है। ब्रिक्स के भीतर सक्रिय रहते हुए भारत समानांतर रूप से क्वाड, जी - 20 और अन्य पश्चिमी मंचों पर भी सहभागिता बनाए रखता है। यह नीति भारत को किसी एक शक्ति-केंद्र पर निर्भर होने से बचाती है तथा उसे स्वतंत्र नीति-निर्माण की क्षमता प्रदान करती है। ब्रिक्स विस्तार के संदर्भ में भारत ने स्पष्ट किया है कि मंच का उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि समावेशी बहुपक्षवाद है। चीन की आर्थिक एवं सामरिक शक्ति ब्रिक्स में प्रभावी है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया चीन-प्रधान एजेंडा को संतुलित करने की है। निर्णय-निर्माण में सर्वसम्मति की परंपरा को बनाए रखना। एजेंडा-निर्धारण में विकास, जलवायु, स्वास्थ्य एवं वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देना। सीमा विवाद एवं इंडो-पैसिफिक प्रतिस्पर्धा को ब्रिक्स के दायरे से बाहर रखना। इस प्रकार भारत प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करता है। भारत स्वयं को "ग्लोबल साउथ की आवाज" के रूप में प्रस्तुत कर रहा है[5]। ब्रिक्स विस्तार से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिससे भारत को विकास, ऋण राहत, खाद्य सुरक्षा और जलवायु न्याय जैसे मुद्दों पर नेतृत्व करने का अवसर मिला है। यह रणनीति भारत की सॉफ्ट पावर और विकास सहयोग मॉडल जैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करती है। ब्रिक्स के नव-विस्तारित ढांचे में ऊर्जा-संपन्न देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति समझौतों, निवेश सहयोग और स्थानीय मुद्रा व्यापार की

संभावनाओं को मजबूत करने की है। पश्चिम तनाव के बीच भारत ने संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने यूक्रेन संकट पर संवाद एवं कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया, परंतु प्रत्यक्ष निंदा से बचते हुए अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखी। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि भारत ब्रिक्स के भीतर अपनी भूमिका निभाते हुए भी अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य साझेदारों से दूरी नहीं बनाना चाहता। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की माँग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व और विकासशील देशों के हितों की रक्षाकृये सभी भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताएँ हैं। ब्रिक्स मंच भारत को इन लक्ष्यों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

किसी भी वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका के लिए आंतरिक शक्ति आवश्यक है। अतः भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया में शामिल हैं - आर्थिक विकास एवं विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, रक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना और तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा संक्रमण एवं हरित विकास[6]। ब्रिक्स विस्तार के संदर्भ में भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया संतुलन, स्वायत्तता और बहुआयामी सहभागिता पर आधारित है। भारत न तो किसी गुटीय ध्रुवीकरण का भाग बनना चाहता है और न ही वैश्विक शक्ति-संतुलन की प्रक्रिया से अलग रहना चाहता है। इस प्रकार, भारत की रणनीति "सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा" पर आधारित है जहाँ वह ब्रिक्स को एक रचनात्मक मंच के रूप में उपयोग कर अपने राष्ट्रीय हितों, वैश्विक प्रतिष्ठा और विकास लक्ष्यों को सशक्त करता है।

निष्कर्ष : भूराजनीतिक परिवर्तनों के वर्तमान दौर में विश्व व्यवस्था एक गहन संक्रमणकाल से गुजर रही है। शीत युद्धोत्तर एकध्रुवीय संरचना, जिसमें पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व स्पष्ट था, अब क्रमशः बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। इसी परिवर्तित परिदृश्य में ब्रिक्स का विस्तार केवल एक संगठनात्मक वृद्धि नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन के पुनर्संरचना का संकेतक है[7]। ब्रिक्स विस्तार ने एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के अनेक देशों को एक साझा मंच पर लाकर वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज को अधिक सशक्त बनाया है। यह विस्तार वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक व्यवस्थाओं में संतुलन स्थापित करने के प्रयास का प्रतीक है, जो पारंपरिक पश्चिम-केंद्रित ढांचे के विकल्प के रूप में उभर रहा है। इस प्रकार ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक समूह न रहकर, वैश्विक शासन सुधार, विकासात्मक वित्त और बहुपक्षीय संतुलन की व्यापक आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बन चुका है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स विस्तार अवसरों और चुनौतियों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। एक ओर यह भारत को वैश्विक दक्षिण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने, विकासशील देशों के हितों को संगठित करने तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी कूटनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभाव, सदस्य देशों की वैचारिक विविधता और वैश्विक शक्ति-प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाए रखना एक जटिल रणनीतिक चुनौती भी है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'बहु-संरेखण' पर आधारित रही है। अतः ब्रिक्स के भीतर सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा इंडो-पैसिफिक सहयोगियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भारत अत्यधिक किसी एक ध्रुव की ओर झुकता है, तो उसकी व्यापक वैश्विक नीति और आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। ब्रिक्स विस्तार का एक महत्वपूर्ण आयाम ऊर्जा एवं संसाधन-सुरक्षा से भी जुड़ा है। नव-प्रवेशित देशों के माध्यम से ऊर्जा-समृद्ध क्षेत्रों के साथ सहयोग की संभावनाएँ बढ़ी हैं, जिससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में स्थिरता आ सकती है। साथ ही, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय तंत्रों का विकास डॉलर-निर्भर वैश्विक वित्तीय संरचना के समांतर एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है। किन्तु यह प्रक्रिया सहज नहीं है वित्तीय स्थिरता, विनिमय दर की अस्थिरता तथा वैश्विक बाजारों की प्रतिक्रिया जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्ण रणनीति अपनानी होगी। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आर्थिक राष्ट्रवाद या वैचारिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बने बिना, व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाए।

साथ ही, ब्रिक्स के भीतर शक्ति-संतुलन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चीन की आर्थिक एवं सामरिक क्षमता उसे समूह में प्रभावशाली बनाती है, जबकि भारत की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स किसी एक राष्ट्र-प्रधान मंच में परिवर्तित न हो। भारत को संस्थागत लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और नियम-आधारित बहुपक्षवाद के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हुए समूह में संतुलनकारी भूमिका निभानी होगी। इसके अतिरिक्त, सदस्य देशों की भिन्न-भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएँ और विदेश नीति प्राथमिकताएँ सामूहिक निर्णय-निर्माण को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। इस स्थिति में भारत की कूटनीतिक दक्षता, मध्यस्थता कौशल और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। समग्रतः, ब्रिक्स विस्तार को एक अवसर और परीक्षा दोनों के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत को बदलती वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने, बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा विकासशील राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने का अवसर देता है[8]। साथ ही, यह भारत की विदेश नीति की परिपक्वता, संतुलनकारी क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता की भी परीक्षा लेता है। यदि भारत विवेकपूर्ण, संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है, तो ब्रिक्स विस्तार उसके लिए वैश्विक नेतृत्व, आर्थिक प्रगति और कूटनीतिक सुदृढ़ता का माध्यम बन सकता है। इस प्रकार, भूराजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में ब्रिक्स विस्तार न केवल वैश्विक शक्ति-संरचना के पुनर्गठन का प्रतीक है, बल्कि भारत के लिए एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर का द्योतक भी है, जिसे दूरदर्शिता, संतुलन और रणनीतिक सूझ-बूझ के साथ साधा जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :

1. लिस्सोवोलिक, या. डी., ब्रिक्स-प्लस द न्यू फोर्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एनालिटिक्स, 14(1), 2023, 138-148.
2. वूरी, एफ. डी., ब्रिक्सः द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर इन ए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, 2023.
3. लिस्सोवोलिक, वाई, ब्रिक्स एक्सपैंशनः न्यू जियोग्रफीज एंड स्फीयर्स ऑफ कोऑपरेशन, ब्रिक्स जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 5(1), 2024, 1-12.
4. ओकिंडो, विन्सेंट, ब्रिक्स-द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अनवील्डः अनरेवलिंग द राइज ऑफ ब्रिक्सः ए पैराडाइम शिफ्ट इन ग्लोबल डायनामिक्स, 2023, 1-128.
5. सैंटोस, पेड्रो, द नेक्स्ट ऑर्डर ब्रिक्सः एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल पावर, 2025, 1-158.
6. जर्मन, नुनेज, ब्रिक्सः स्ट्रेटेजीज फॉर ए न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्विलग्राम, क्विलग्राम, 2025, 1-180.
7. पकर्डी, क्लाउडियो, ब्रिक्सः आर्किटेक्ट्स ऑफ ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर - एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ, चैलेंजेस, एंड पोटेंशियल ऑफ इमर्जिंग जायंट्स इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाउडियो पकर्डी, 2024, 1-220.
8. स्टूएनकेल, ओलिवर, द ब्रिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, लेक्सिंग्टन बुक्स, 2021 (द्वितीय संस्करण), 61-110.

•